IJAREEIE

e-ISSN: 2278-8875
p-ISSN: 2320-3765

International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering

Volume 13, Issue 4, April 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.317

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

मेक इन इण्डिया और विनिर्माण क्षेत्र

BHUPENDRA CHOUDHARY

MA, B.Ed, NET (ECONOMICS), AJMER, RAJASTHAN, INDIA

सार

'मेक इन इंडिया' मुख्यत: निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नये क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है।

परिचय

मेक इन इण्डिया अर्थात 'भारत में बनाओ' अभियान भारत सरकार की पहल पर एक बहुआयामी अभियान है, जिसमें भारत को बनाने का अर्थ निहित है। 'मेक इन इण्डिया' अभियान की साफल्य से ही 'मेड इन इण्डिया' अर्थात 'भारत में निर्मित' का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण होगा। इस अभियान का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने का है। यह संकल्प औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। इस अभियान का सीधा सा अर्थ है- उत्पादन बढ़ाओ, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करो, क्रयशक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। इस अभियान से सम्पूर्ण विश्व की लगभग 300 प्रमुख कम्पनियों को जोड़ने की योजना है और इसके लिए मुख्य 25 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जिनमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है। मेक इन इंडिया पहल इसकी प्राचीनता को संरक्षित और प्रोत्साहित कर रही है, साथ ही इसकी नवीनता और आधुनिकता को भी मजबूत करेगा।[1]

इस अभियान को वास्तविक आधार पर सफल बनाने के लिए विदेशी उद्यमियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस अभियान का संकल्प देश के विकास के नए रास्ते खोलने में सक्षम है। मार्ग में आने वाली विघ्नों को दूर कर निवेश की नई सम्भावनाओं से यह अभियान वास्तव में, शान्ति, सुरक्षा एवं समृद्धि का मूलमन्त्र सिद्ध होगा।[1,2,3]

योजना से लाभ

1.भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना:-'मेक इन इंडिया'के माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी जिससे की भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके। 2.भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:-इसके बढ़ोतरी होने से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 16% का योगदान देता है और सरकार का लक्ष्य इसे 2020 तक 25% करना है। 3.रोजगार के अधिक अवसर:-इसके माध्यम से सरकार नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण युवाओं को मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी जिससे कि देश में नयी स्टार्ट उप कंपनियों का विकास हो सके जो कि आगे चलकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।इसके तहत कुल 25 क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा जिससे लगभग दस मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।इतने लोगों के रोजगार मिलने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास हो सकेगा।

4. अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका:- सरकार द्वारा 13 फरवरी 2016 को मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएमआरडीए ग्राउंड में आयोजित"मेक इन इंडिया वीक" के लंबे बहु क्षेत्रीय औद्योगिक में 68 देशों के 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। DIPP के सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि उन्हें 15.2 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताओं (investment commitments) और 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पूछताछ (investment inquiries) प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र को 8 लाख करोड़ रुपये (120 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश मिला। 5. भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा:-'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत अगस्त 2015 में,हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प (Irkut Corp) कम्पनी से वार्ता शुरू की। [2]

मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद निवेश के लिए भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया और वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसके बाद साल 2016 में पुरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने करीबन 60 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो विश्व के कई बड़े विकसित देशों से कहीं अधिक था।[3]

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

इलेक्ट्रॉनिक 2020 तक अमेरिका $ 400 अरब के लिए तेजी से वृद्धि की उम्मीद हार्डवेयर के लिए मांग के साथ, भारत संभावित एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनने की क्षमता है।सरकार ने एक स्तर के खेल मैदान बनाने और एक अनुकूल माहौल प्रदान करके 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध शून्य आयात को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।[4,5,6]

इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर, 2014 को शुरू की "भारत में बनाओ।" [1] 29 दिसंबर 2014, एक कार्यशाला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो मोदी, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ही विभिन्न उद्योग के नेताओं ने भाग लिया द्वारा आयोजित किया गया था। [2]

पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं। [3] पहल भी उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। [4] [5] पहल भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। [3]

अभियान Wieden + कैनेडी द्वारा डिजाइन किया गया था। [6] पहल के तहत 25 क्षेत्रों और एक वेब पोर्टल पर ब्रोशर जारी किए गए। इससे पहले पहल शुरू किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी टोपियां आराम दिया गया था। लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था और लाइसेंस की वैधता तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था। विभिन्न अन्य मानदंडों और प्रक्रियाओं को भी निश्चिंत थे। [7]

अगस्त 2014 में, भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी। रक्षा क्षेत्र में पहले से अनुमति 26% एफडीआई और एफडीआई रेलवे में अनुमति नहीं थी। यह भारत की सैन्य आयात नीचे लाने की आशा में था। इससे पहले, एक भारतीय कंपनी में 51% हिस्सेदारी का आयोजन किया गया होगा, यह बदल गया था तो यह है कि कई कंपनियों के 51% पकड़ सकता है। [8]

सितंबर 2014 और नवंबर 2015 के बीच, सरकार ₹ 1.20 लाख करोड़ प्राप्त (US $ 18 अरब डॉलर) भारत में विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स में इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव के लायक है। [9]

2015 की अप्रैल-जून तिमाही में देश में भेज दिया smartphones की 24.8% भारत में किए गए थे, ऊपर 19.9% पिछली तिमाही से।[7,8,9]

भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद अगले ही साल भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। साल 2015 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में ₹ 4.06 लाख करोड़ (US $ 63 अरब डॉलर) प्राप्त हुए, जो चीन से भी ज्यादा था।

भारत में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के अक्टूबर महीने में 13 फीसदी अधिक जापानी कंपनियों ने व्यापार आरम्भ किया। नवंबर 2014 में भारत में फैक्ट्री विकास दर की रफ्तार अधिकतम रही थी।

व्यापार करने में आसानी

भारत, व्यापार सूचकांक जून 2014 और जून 2015 में भारत से इस अवधि को कवर करने के लिए विश्व बैंक के 2016 आराम में 189 देशों की 130 से बाहर 2015 सूचकांक में 134 वें स्थान पर था शुमार है। [19]

भारत 2009 की रिपोर्ट में विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस में 17 भारतीय शहरों के एक सर्वेक्षण में भारत में व्यापार करने के लिए शीर्ष पांच सबसे आसान शहरों के रूप में लुधियाना , हैदराबाद, भुवनेश्वर , गुड़गांव, अहमदाबाद और स्थान पर रहीं। [20]

प्रतिक्रियायें

जनवरी से जून 2015 जनवरी 2015 में, स्पाइस समूह ने कहा कि यह ₹ 5 अरब (अमेरिका $ 74 मिलियन) के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश में एक मोबाइल फोन विनिर्माण इकाई शुरू होगा। एक समझौता ज्ञापन पर स्पाइस समूह और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

जनवरी 2015 में, ह्यून बच्चों हाँग, राष्ट्रपति और सैमसंग दक्षिण एशिया के सीईओ, कलराज मिश्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई), के साथ मुलाकात की एक संयुक्त पहल है जिसके तहत 10 "एमएसएमई-सैमसंग तकनीकी स्कूल" चर्चा करने के लिए भारत में स्थापित किया जाएगा। फरवरी में सैमसंग ने कहा है कि नोएडा में अपने संयंत्र में सैमसंग Z1 निर्माण होगा।

फरवरी 2015 में, हिताची ने कहा कि यह पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहा जाता है कि यह 13,000 करने के लिए 10,000 से भारत में अपने कर्मचारियों में वृद्धि होगी और यह ¥ 210 अरब करने के लिए 2013 में ¥ 100 अरब से भारत से अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है एक ऑटो घटक संयंत्र 2016 में चेन्नई में स्थापित किया जाएगा।

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

फरवरी 2015 में, हुआवेई बेंगलुरु में एक नए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परिसर में खोला गया। यह अमेरिका के $ 170 मिलियन का निवेश किया था अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए। [25] [26] यह चेन्नई में एक टेलीकॉम हार्डवेयर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है, जो अनुमोदन की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। [27] इसके अलावा फरवरी में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा है कि यह पहल के तहत भारत में झींगा किसानों को झींगा अंडे की आपूर्ति करने में दिलचस्पी थी। [28] फरवरी 2015 में, Xiaomi श्री सिटी में एक फॉक्सकॉन रन की सुविधा में विनिर्माण smartphones शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ प्रारंभिक वार्ता शुरू किया। 11 अगस्त 2015, कंपनी ने घोषणा की है कि पहली विनिर्माण इकाई परिचालन किया गया था और Xiaomi Redmi 2 प्रधानमंत्री, कि एक स्मार्टफोन की सुविधा में इकट्ठा किया गया था की शुरुआत की। [29] Xiaomi भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु जैन ने कहा, "हम घोषणा की भारत में हमारे मेक इस वर्ष 2015 [30] हमने सोचा कि यह हमारे दो साल लेने के लिए इस विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की शुरुआत में योजना बना रही है। लेकिन हैरत की बात है कि हम स्थापित करने में सक्षम थे सब कुछ है और हमारे उत्पादन सात महीने के भीतर शुरू कर दिया। "[10,11,12]

जून 2015, फ्रांस स्थित एलएच उड्डयन भारत में विनिर्माण संयंत्र ड्रोन के निर्माण के लिए स्थापित करने के लिए OIS उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। [32]

जुलाई से दिसंबर 2015 8 अगस्त को 2015, फॉक्सकॉन घोषणा की कि वह अमेरिका $ 5 अरब पांच साल से अधिक का निवेश करेगी एक अनुसंधान और विकास और महाराष्ट्र में उच्च तकनीक अर्धचालक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए। [33] [34] एक सप्ताह पहले, जनरल मोटर्स ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका $ 1 अरब राज्य में ऑटोमोबाइल के निर्माण शुरू करने के लिए निवेश होगा की तुलना में कम है। [35]

18 अगस्त 2015, लेनोवो घोषणा की कि वह चेन्नई के निकट श्रीपेरंबुदूर में एक संयंत्र, सिंगापुर स्थित अनुबंध निर्माता फ्लेक्सट्रॉनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा चलाए में मोटोरोला स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र शुरू हो गया था लेनोवो और मोटोरोला के लिए अलग लाइनों के निर्माण, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन दिया है, और उत्पाद परीक्षण। सुविधा में निर्मित पहला स्मार्टफोन मोटोरोला मोटो ई (2 पीढ़ी) की 4 जी संस्करण था। [36] [37] 16 अक्टूबर 2015, बोइंग के चेयरमैन जेम्स McNerney ने कहा है कि कंपनी के लड़ाकू विमानों को इकट्ठा और भारत में अपाचे या चिनूक हेलीकाप्टर रक्षा या तो कर सकता है। [38] कंपनी ने भारत में एफ / ए -18 सुपर हॉर्नेट निर्माण करने के लिए यदि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) इसे खरीदने के लिए थे तैयार है। [39]

नवंबर 2015 में, ताइवान के अजगर कॉर्प, जो इस तरह के ब्लैकबेरी, एचटीसी और मोटोरोला जैसी कंपनियों के लिए उपकरणों बनाता है, घोषणा की कि वह नोएडा में एक नया कारखाना, उत्तर प्रदेश में उपकरणों के निर्माण शुरू होगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "सरकार के अभियान, देश की बढ़ती खपत के साथ मिलकर 'मेक इन इंडिया', भारतीय विनिर्माण क्षेत्र सेक्टरों में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक उत्कृष्ट मामला बन गया है।" [40]

30 नवंबर 2015 को रेल मंत्रालय एल्सटॉम और जीई परिवहन लायक ₹ 400 अरब (यूएस $ 5.9 अरब) स्थापित करने के मधेपुरा और Marhaura में लोकोमोटिव निर्माण कारखानों बिहार में। [41] के साथ औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए

दिसंबर 2015 में, क्वालकॉम ने घोषणा की कि यह एक "भारत में डिजाइन" कार्यक्रम में मदद करने के लिए क्षमता के साथ दस भारतीय हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऊपर संरक्षक अभिनव समाधान के साथ आते हैं और उन्हें पैमाने तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। क्वालकॉम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वे सितंबर 2015 में सिलिकॉन वैली के उत्तरार्द्ध की यात्रा के दौरान ऐसा होता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कंपनी बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब की स्थापना की चयनित कंपनियों के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करने के लिए होगा। [42] एक ही महीने में, माइक्रोमैक्स ने घोषणा की कि यह होगा ₹ 3 अरब (अमेरिका $ 45 मिलियन) की लागत से राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नए विनिर्माण इकाइयों। पौधों 2016 में कामकाज शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक 3,000-3,500 लोगों को रोजगार देगा। [43] [44]

दिसंबर 2015 में भारत को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की यात्रा के बाद यह घोषणा की गई है कि जापान को एक अमेरिकी 'जापान-भारत मेकअप में भारत-विशेष वित्त सुविधा "कहा जाता है भारत से संबंधित परियोजनाओं में मेक के लिए $ 12 अरब कोष की स्थापना की जाएगी। [45] देर से दिसंबर में, फोन निर्माता विवो मोबाइल भारत ग्रेटर नोएडा में एक संयंत्र में विनिर्माण smartphones शुरू किया। संयंत्र में 2,200 लोग कार्यरत हैं। [46]

एक रक्षा सौदा दिसंबर 2015 में रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो कामोव केए-226 बहु-भूमिका हेलीकाप्टर भारत में बनाया जा रहा है देखेंगे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह व्यापक रूप से पहले रक्षा सौदा वास्तव में भारत अभियान में मेक के तहत हस्ताक्षर किए जाने के रूप में देखा जाता है। [13,14,15]

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

Make in India Week

" make in India week" घटना 13 से मुंबई में बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स फ़रवरी 2016 सप्ताह तक बहु -क्षेत्रीय औद्योगिक 68 देशों से 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू , विदेशी सरकार के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया और इसे एमएमआरडीए मैदान में आयोजित किया गया था और 72 देशों से व्यापार टीमों। 17 भारतीय राज्यों , ज्यादातर भाजपा शासित भी आयोजित Expos। घटना के पास में डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि यह ₹ 15.2 लाख करोड़ (US $ 230 अरब) निवेश प्रतिबद्धताओं और निवेश पूछताछ के लायक ₹ 1.5 लाख करोड़ रुपये (22 अरब अमेरिकी $) की कीमत पर प्राप्त किया था। महाराष्ट्र के अन्य सभी निवेश का ₹ 8 लाख करोड़ रुपये (120 अरब अमेरिकी $) प्राप्त राज्यों का नेतृत्व किया। [49] [50]

योजना

अगस्त 2015 में , हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत कार्यक्रम के तहत मेक सुखोई एसयू -30 एमकेआई लड़ाकू विमान के 332 घटकों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए रूस के Irkut कॉर्प के साथ वार्ता शुरू की। इन घटकों को भी बुलाया लाइन बदलने की इकाइयों (LRUs) दोनों महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण घटकों को देखें और इस तरह के रेडियो और रडार के रूप में चार प्रमुख सिर में गिर जाते हैं ; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम ; यांत्रिक प्रणाली और उपकरण प्रणाली है। [51]

रक्षा मंत्रालय के एक 600 अरब (8.9 अरब अमेरिकी $) अनुबंध के लिए डिजाइन और भारत में एक लड़ाई पैदल सेना का मुकाबला वाहन (FICV) के निर्माण के लिए नीलामी की जाती है। अनुबंध 2016 में सम्मानित किया जाएगा [52]

फ़रवरी 2016 in , लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि यह था " भारत में एफ -16 के निर्माण और भारत पहल में मेक का समर्थन करने के लिए तैयार " है, हालांकि यह किसी भी समय सीमा की घोषणा नहीं की।

FDI

2015 में, भारत अमेरिका एफडीआई में 63 अरब $ प्राप्त किया।

विचार-विमर्श

मेक इन इंडिया' का मानना है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात 'कारोबार करने की सुविधा' है। कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कई इनीशिएटिव पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य पूरे कारोबारी चक्र के दौरान इंडस्ट्री को डी-लाइसेंस और डी-रेग्युलेट करना है।[16,17,18]

नया बुनियादी ढांचा: उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक और सुविधाजनक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण जरूरत है। सरकार आधुनिक हाई-स्पीड कम्युनिकेशन और इंटग्रेटेड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स के साथ ही उत्कृष्ट तकनीक पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज़ बनाने का इरादा रखती है। इंडस्ट्रियल कल्स्टर्स में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी।
नए क्षेत्र: 'मेक इन इंडिया' ने विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवा गतिविधियों में 25 क्षेत्रों की पहचान की है और इस बारे में इंटरेक्टिव वेब पोर्टल और पेशवर ढंग से तैयार किए गए ब्रोशर्स के माध्यम से विस्तृत सूचनाएं साझा की जा रही हैं।
नई सोच: उद्योग सरकार को एक नियामक के रूप में देखने के आदी रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' का मकसद उद्योगों के साथ सरकार के संवाद में आमूलचूल परिवर्तन लाकर इस सोच को बदलना है। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के साथ साझेदार बनेगी। हमारा नज़रिया एक फैसिलिटेटर का होगा और एक रेग्युलेटर का नहीं।
'मेक इन इंडिया' ने भारत में कारोबारी दिग्गजों के साथ ही फॉरेन लीडर्स के बीच भी अपने प्रशंसक तैयार किये हैं। इस ऐतिहासिक पहल में दुनिया भारत के साथ साझेदारी करने की इच्छुक है।
हमने एक मैन्युफैक्चरिंग इनीशिएटिव का रोडमैप तैयार किया है, जो हाल के इतिहास में किसी भी देश द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहल है। ये सार्वजनिक-निजी साझेदारी की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। भारत के वैश्विक साझेदारों को शामिल करने के लिए भी इस सहयोगी मॉडल का सफलतापूर्वक विस्तार किया गया।
थोड़े समय में ही, अतीत का घिसेपिटा और बाधक ढांचा खत्म हो गया और उसकी जगह एक पारदर्शी तथा लोगों के अनुकूल व्यवस्था ने ले ली। नई व्यवस्था निवेश जुटाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, कौशल विकास, आईपी संरक्षण और बेहतरीन विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण में मददगार है।
निवेश की सीमा और नियंत्रण को आसान बनाने के साथ ही भारत के मूल्यवान क्षेत्र – रक्षा, निर्माण और रेलवे – अब वैश्विक साझेदारी के लिए खुल गए हैं। रक्षा क्षेत्र में नीति को उदार बनाया गया और एफडीआई सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

गया। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 24% तक पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट की अनुमति दी गई। रक्षा क्षेत्र में अलग-अलग मामलों के आधार पर अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट तकनीक के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। कुछ विशेष रेल ढांचागत परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट के तहत निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए 100% एफडीआई की भी मंजूरी दी गई। कारोबार को आसान बनाने के लिए सरलीकृत कर प्रणाली बनाई गई। 22 इनपुट या कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी ने विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण लागत मंय कमी आई। गार को दो वर्षों के लिए टाल दिया गया। टेक्नॉलॉजी आसानी से आ सके, इसके लिए तकनीकी सेवाओं की रायल्टी और शुल्क पर आयकर की दर को 25% से घटाकर 10% किया गया।
वस्तुओं के निर्यात और आयात के लिए जरूरी दस्तावेजों को घटाकर तीन कर दिया गया। भारत सरकार की 14 सेवाएं ई-बिज़ के ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से मिलने लगीं। निवेशकों को गाइड करने के लिए इनवेस्टर्स फैसिलिटेशन सेल बनाई गई। ई-बिज़ पोर्टल के जरिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को 24X7 के आधार पर ऑनलाइन किया गया। औद्योगिक लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर तीन वर्ष की गई। रक्षा उत्पादों के प्रमुख कंपोनेंट्स की सूची को औद्योगिक लाइसेंस से अलग किया गया। नए बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी/सहमति की जरूरत को खत्म कर दिया गया।
इसके अलावा भारत सरकार विनिर्माण में तेजी लाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए देश भर में गलियारों का एक पंचकोण (पैंटागन) बना रही है।

परिणाम

हाल ही में एक दर्जन से अधिक "प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण" शर्तें, जो स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोकती थीं, का निराकरण एवं 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूरी प्रदान की गई।

- ये शर्तें सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 का उल्लंघन थीं, जो स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने और आय एवं रोज़गार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जारी की गई थीं।
  - वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।
  - इसका नेतृत्त्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
  - यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
  - मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियांँ हासिल की हैं। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं।
- उद्देश्य:
  - नए औद्योगीकरण के लिये विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चीन से आगे निकलने के लिये भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना।
  - मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12-14% वार्षिक करने का लक्ष्य।
  - देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना।
  - वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजित करना।
  - निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- प्रमुख चार स्तंभ:
  - नई प्रक्रियाएँ:
    - 'मेक इन इंडिया' उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को एकमात्र सबसे महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता देती है, जिसके लिये पहले ही कई पहलें की जा चुकी हैं।
    - इसका उद्देश्य व्यवसाय की संपूर्ण अवधि में इस क्षेत्र को लाइसेंस और विनियमन से मुक्त करना है।

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

- नई अवसंरचना:
  - इस क्षेत्र का विस्तार करने के लिये सरकार ने औद्योगिक गलियारों का निर्माण, मौजूदा बुनियादी ढाँचे का उन्नयन और त्वरित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करने की योजना बनाई है।
- नए क्षेत्र: [19]
  - "मेक इन इंडिया" द्वारा विनिर्माण, बुनियादी ढाँचे और सेवा गतिविधियों के लिये 27 उद्योगों की पहचान की गई है तथा एक इंटरैक्टिव वेब पेज एवं पैम्फलेट के माध्यम से इस संबंध में व्यापक जानकारी दी जा रही है।
- नई सोच:
  - "मेक इन इंडिया" पहल मूल रूप से व्यवसाय के साथ सरकार के काम करने के तरीके को बदलना चाहती है।
  - सरकार देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये विभिन्न उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी और नियामक रुख की बजाय एक सुविधाजनक तरीका अपनाएगी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह: विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये भारत सरकार ने एक उदार और खुली नीति लागू की है जो स्वचालित मार्ग के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों को FDI के लिये सुलभ बनाती है।
  - वर्ष 2014-2015 में भारत में FDI अंतर्वाह 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर था और तब से लगातार आठ वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।
    - वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI दर्ज किया गया।
  - आर्थिक सुधारों और पिछले वर्षों (2022-23) में व्यापार करने में सुगमता के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI): 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं को मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2020-21 में लॉन्च किया गया था।

मेक इन इंडिया का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है।घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है ताकि 125 करोड़ की आबादी वाले मजबूत भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा हों। इससे एक गंभीर व्यापार में व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसमें किसी नवाचार के लिए आवश्यक दो निहित तत्वों– नये मार्ग या अवसरों का दोहन और सही संतुलन रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना शामिल हैं। राजनीतिक नेतृत्व के व्यापक रूप से लोकप्रिय होने की उम्मीद है। लेकिन 'मेक इन इंडिया' पहल वास्तव में आर्थिक विवेक, प्रशासनिक सुधार के न्यायसंगत मिश्रण के रूप में देखी जाती है। इस प्रकार यह पहल जनता जनादेश के आह्वान- 'एक आकांक्षी भारत' का समर्थन करती है।

प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य

- मध्यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में 12-14 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25 प्रतिशत करना।
- विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
- ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना।
- घरेलू मूल्य संवर्द्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।
- भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।

सकारात्मक बातें

- भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुका है।
- यह देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है और उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2020 तक यह दुनिया की सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा।

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

- अगले दो तीन दशकों तक यहां की जनसंख्या वृद्धि उद्योगों के अनुकूल रहेगी। जनशक्ति काम करने के लिए बराबर उपलब्ध रहेगी।
- अन्य देशों के मुकाबले यहां जनशक्ति पर कम लागत आती है।
- यहां के व्यावसायिक घराने उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से, भरोसेमंद तरीकों से और व्यावसायिक रूप से काम करते हैं।
- घरेलू मार्किट में यहां तगड़ा उपभोक्तावाद चल रहा है।
- इस देश में तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताएं मौजूद है और उनके पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का हाथ है।
- विदेशी निवेशकों के लिए बाजार खुला हुआ है और यह काफी अच्छी तरह से विनियमित है।

जनशक्ति प्रशिक्षण

कोई भी उत्पादन क्षेत्र बिना कुशल जनशक्ति के सफल नहीं हो सकता। इसी सिलसिले में यह संतोषजनक बात है कि सरकार ने कौशल विकास के लिए नये उपाय किये हैं। इनमें से निश्चय ही गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन रुकेगा और शहरी गरीबों का अधिक समावेशी विकास हो सकेगा। यह उत्पादन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

नये मंत्रालय – कौशल विकास और उद्यमियता ने राष्ट्रीय कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन शुरू कर दिया है। ये ध्यान देने की बात है कि मोदी सरकार ने ग्राम विकास मंत्रालय के तहत एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम का नाम बीजेपी के नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। नये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 1500 से 2000 तक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का कार्यक्रम है। इस सारी परियोजना पर 2000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। यहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारूप में संचालित की जाएगी।

नये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत युवा वर्ग को उन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनकी विदेशों में मांग है। जिन देशों को नजर में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है, उनमें स्पेन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया शामिल हैं। सरकार ने हर साल लगभग तीन लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रकार से वर्ष 2017 के आखिर तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

अन्य जो उपाय किये जाने हैं उनमें मूल सुविधाओं और खासतौर से सड़कों और बिजली का विकास करना शामिल है। लंबे समय तक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सॉफ्टवेयर कंपनियां भारत में इसलिये काम करना पसंद करती थी, क्योंकि यहां एक विस्तृत मार्किट और नागरिकों की खरीद क्षमता है। इसके अलावा इस देश में उत्पादन सुविधायें भी मौजूद हैं। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति, नौकरशाहों और उद्यमियों का अनुकूल रवैया, कुशल जनशक्ति और मित्रतापूर्ण निवेश नीतियां मौजूद हैं।

निष्कर्ष

इसी संदर्भ में सरकार की दिल्ली और मुम्बई के बीच एक औद्योगिक गलियारा विकसित करने की कोशिशों की जा रहीं हैं। सरकार बहुपक्षीय नीतियों पर काम कर रही है। इनमें मुख्य संयंत्रों और मूल सुविधाओं के विकास में सम्पर्क स्थापित करने और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने, उच्च क्षमता की परिवहन सुविधा विकसित करने का काम शामिल है। इन क्षेत्रों में काम करते हुए सरकार ने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 निगम ऐसे हैं, जिनके बारे में सरकार का विचार है कि छः निगमों को बंद कर दिये जाने की जरूरत है। 1000 करोड़ रूपये की लागत पर इन निगमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जा रही है। यह एक बारगी समझौता होगा।

सरकार द्वारा संचालित जिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को फिर से काम लायक बनाने का फैसला किया गया है। उनमें एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, नेपा लिमिटेड, नगालैंड पेपर एंड पल्प कंपनी लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल्स शामिल हैं।[20]

संदर्भ

1. "लुक ईस्ट, लिंक वेस्ट, मेक इन इंडिया लॉन्च पर पीएम मोदी ने कहा" । हिंदुस्तान टाइम्स । 25 सितंबर 2014। मूल से 25 सितंबर 2014 को संग्रहीत।
2. ^ 'मेक इन इंडिया' पर ध्यान दें" . बिजनेस स्टैंडर्ड । 25 सितंबर 2014 । 27 फरवरी 2015 को लिया गया ।
3. ^ "मेक इन इंडिया - हमारे बारे में" । www.facebook.com . 26 मई 2018 को लिया गया .
4. ^ "भारत में निर्माण कार्यक्रम, भारत में निर्माण पहल के बारे में सब कुछ" ।
5. ^ बाबू, एम. सुरेश (20 जनवरी 2020)। "क्यों 'मेक इन इंडिया' विफल हो गया है" । हिन्दू । आईएसएसएन 0971-751X . 21 जनवरी 2020 को पुनःप्राप्त .
6. ^ [ए] [बी]"मोदी के 'मेक इन इंडिया' ने 2 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है" , रॉयटर्स , 18 फरवरी 2016

| e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.317|| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

||Volume 13, Issue 4, April 2024||

| DOI:10.15662/IJAREEIE.2024.1304040 |

7. ^ [ए] [बी]"'मेक इन इंडिया वीक' को ₹15.2 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं मिलीं" , द इकोनॉमिक टाइम्स , 18 फरवरी 2016
8. ^ [ए] [बी]अब्बास, मुंतज़िर. "मेक इन इंडिया: केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में ₹1.20 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले" । टाइम्सऑफइंडिया-इकोनॉमिकटाइम्स ।
9. ^ "भारत 2015 में चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष एफडीआई गंतव्य बन गया: रिपोर्ट - द इकोनॉमिक टाइम्स" , द इकोनॉमिक टाइम्स , 21 अप्रैल 2016 , 14 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त
10. ^ "सेक्टर" । मेक इन इंडिया। 14 अगस्त 2015 को मूल से संग्रहीत । 1 अक्टूबर 2015 को लिया गया ।
11. ^ "पीएम मोदी का 'मेक इन इंडिया' एक साल का हो गया: आपको इस पहल के बारे में जानने की जरूरत है" । डी.एन.ए. 25 सितंबर 2015.
12. ^ चौधरी, दीपांजन रॉय (14 दिसंबर 2015), "निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापान का $12 बिलियन का 'मेक इन इंडिया' फंड" , टाइम्सऑफइंडिया-इकोनॉमिकटाइम्स
13. ^ "मेक-इन-महाराष्ट्र मिशन 20 लाख नौकरियां पैदा करेगा" , द टाइम्स ऑफ इंडिया , 17 जनवरी 2015
14. ^ [ए] [बी]नया भारत पूरे देश में दिखाई दे रहा है: पीएम मोदी , टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 जनवरी 2018।
15. ^ कारोबार करने में आसानी के मामले में भारत की रैंक में 23 स्थान का सुधार हुआ है। यह अभियान एक पोस्टर अभियान से अधिक है। (प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), [1] , 31-अक्टूबर-2018
16. ^ [ए] संकेतक, प्रमुख आर्थिक (25 जून 2021)। "प्रमुख आर्थिक संकेतक" । आर्थिक सलाहकार का कार्यालय । 18 फरवरी 2022 को मूल से संग्रहीत । 18 फरवरी 2021 को लिया गया ।
17. ^ "राष्ट्रीय आय 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर प्रेस नोट" (पीडीएफ) । mospi.gov.in . 22 अप्रैल 2023 को पुनःप्राप्त .
18. ^ "भारत में व्यापार करने में आसानी" । www.doingbusiness.org . 25 अप्रैल 2016 को लिया गया ।
19. ^ "व्यवसाय करने में आसानी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले भारत की विश्व बैंक रैंकिंग में सुधार किया है" । द फाइनेंशियल एक्सप्रेस । 18 फरवरी 2017.
20. ^ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व्यापार करने में आसानी के चार्ट में शीर्ष पर हैं , बिजनेस स्टैंडर्ड, 31 अक्टूबर 2016।
21. ^ ओईसीडी आर्थिक सर्वेक्षण: भारत 2017 , पृष्ठ 123।

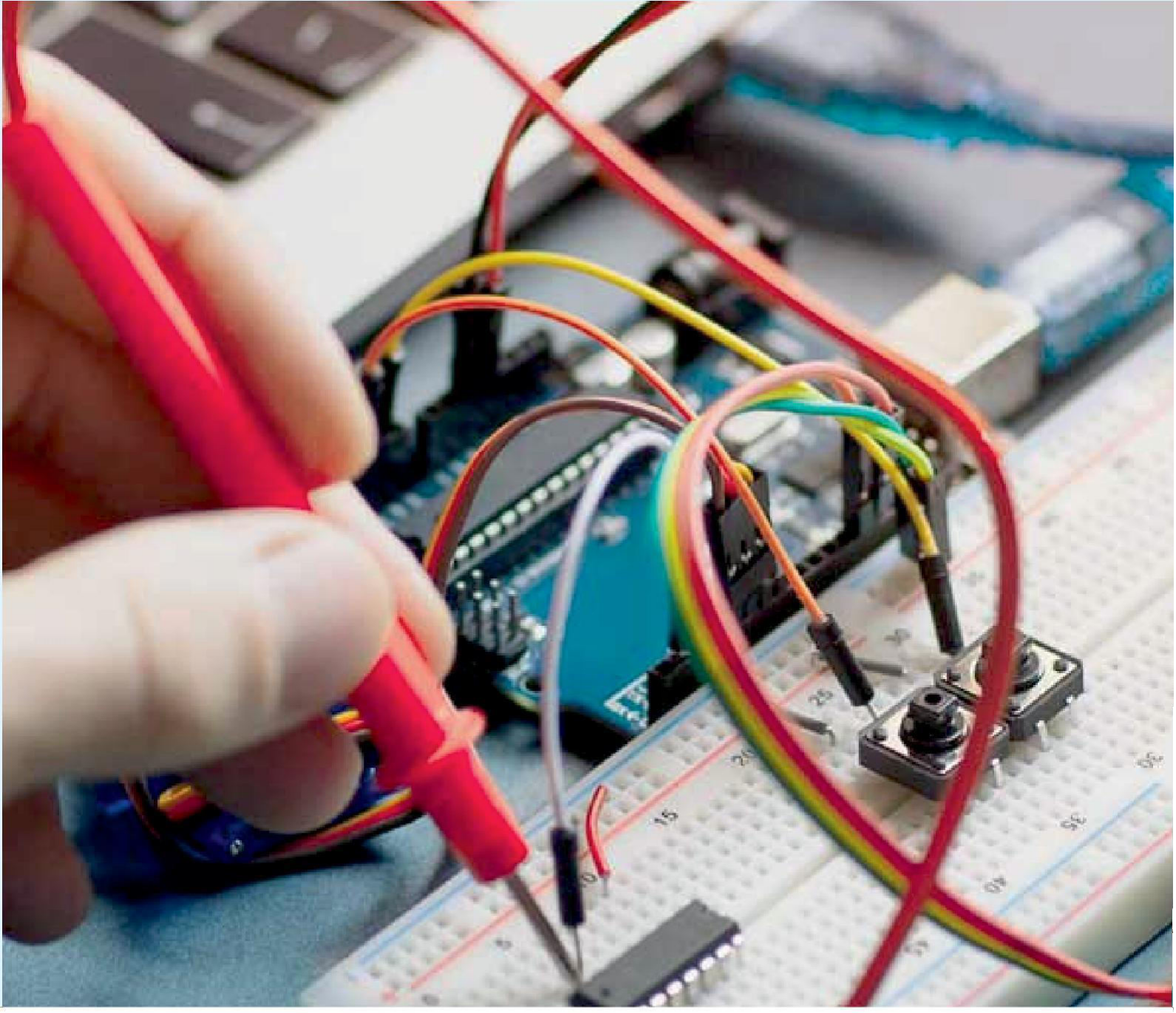

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi cross ref

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research

in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering

9940 572 462 6381 907 438 ijareeie@gmail.com

Scan to save the contact details